ऑस्ट्रेलिया में एक कैदी, विलियम बकली जेल से भागा और उसके बाद उसने अपना लगभग सारा जीवन समुद्र के किनारे एक गुफा में बिताया। जेल से भागने और उसके बाद ज़िंदा रहने की उसकी कहानी रोचक है। बकली पर, जानते बूझते चोरी के कपड़े का थान लेने का आरोप था। हालांकि उसका कहना था कि, वह तो केवल एक महिला के लिए कपड़ा ले जा रहा था, उसे नहीं पता था कि वो चोरी का है। फिर भी उसे 14 साल कैद की सजा दी गई और जेल भेज दिया गया। एच.एम.एस. कैलकटा जहाज से उसे सलिवन्स खाड़ी में सोरैन्टो कॉलोनी ले जाया गया। सन् 1803 में जब उसे पता चला कि उसे टैस्मेनिया भेजा जाएगा तो वह जेल से भाग निकला और स्थानीय वादरॉंग समुदाय के साथ रहने लगा। कहा जाता है कि इस दौरान वो एक गुफा में ही रहा। आज इस गुफा को बकली'ज़ केव (बकली की गुफा) कहते हैं। बत्तीस साल बाद बकली बैलारीन प्रायद्वीप के सेंट लिओनार्ड्स के पास जॉन बैटमैन के शिविर में आया। उसके शरीर पर उसके नाम के पहले अक्षर, ''डब्ल्यु.बी.'' गुदे हुए थे जिससे पुष्टि हुई कि वो विलियम बकली है जो 1803 में जेल से भाग गया था और जिसे मृत मान लिया गया था। बैटमैन ने अपना कैम्प सेंट लियोनार्ड्स से मैलबर्न शिफ्ट कर लिया। बकली को भी बाद में माफी मिल गई। उसने दो साल तक श्वोतों और स्थानीय अबॉरिजिनल्स (मूल निवासियों) के बीच मध्यस्थता का काम किया। पर उसकी निष्टा बंटी हुई थी और दोनों ही पक्ष उस पर भरोसा नहीं करते थे। यहां से मोहभंग होने के बाद वह टैस्मैनिया चला गया। जहां उसने नौकरी की और शादी की। सन् 186 में 76 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई। बकली के फरार होने की कहानी आज भी ऑस्ट्रेलिया में सुनी -सुनाई जाती है और इसके आधार पर एक कहावत भी है, ''बकली'ज़ चांस''।

'सत्तर के दशक जैसी बड़ी मंदी एक बार फिर आयेगी'

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नूरील रूबीनी ने 2023 में आर्थिक मंदी की आशंका जाहिर की

- नूरील रूबीनी ने ही सबसे पहले कड़े शब्दों में 2008 की मंदी की आशंका जहिर की थी।
- नूरील रूबीनी का मानना है कि, अमेरिका और वैश्विक स्तर पर मंदी की शुरुआत इस साल के अंत में होगी, जो 2023 के आखिर तक चल सकती है। यह एक लंबा वक्त होगा, इस दौरान दुनियाभर में इकॉनमी तबाही के मंजर देखे जाएंगे।
- नूरील रूबीनी का मानना है कि, बड़े पैमाने पर ऋण संकट देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि, यह एक छोटी मंदी नहीं होने वाली है। यह गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली मंदी होगी।

वॉशिंगटन, 23 सितम्बर। अमेरिका समेत दुनिया भर में मंदी का सबसे लंबा और बुरा दौर आने वाला है। ये आशंका अर्थशास्त्री नूरील रूबिनी को है। ये वही अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने साल 2008 के आर्थिक संकट की सही भविष्यवाणी की थी। इस मंदी के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो गए थे और बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने लगी थीं। अब एक बार फिर नूरील रूबिनी ने मंदी की आहट पहचान ली है।

नूरील रूबिनी का मानना है कि अमेरिका और वैश्विक स्तर पर मंदी की शुरुआत इस साल के अंत में होगी, जो 2023 के आखिर तक चल सकती है। यह एक लंबा वक्त होगा, इस दौरान दुनियाभर की इकोनॉमी तबाही के मंजर देख सकती है।

महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व की ओर से लगातार ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं। इस पर नूरील रूबिनी ने कहा कि ऐसा लगता है फेड रिजर्व के बाद दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि, बिना हार्ड लैण्डिंग के 20 मुद्रास्फीति दर प्राप्त करना फेडरल रिजर्व के लिए मिशन इम्पॉसिबल लगता है। रूबिनी को उम्मीद है कि, फेड रिजर्व नवंबर और दिसंबर में लगातार ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट तक की बढ़ोतरी करने वाला है। रूबिनी को आशंका है कि कई जोंबी संस्थान, बैंक, कॉरपोरेट, शैडो बैंकों का वजूद खत्म हो सकता है।

उन्होंने कहा कि दुनिया मंदी की चपेट में है तो सरकारों से राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारें पहले से ही अधिक कर्ज में चल रही हैं। रूबिनी इस संकट को 1970 के दशक के हालात की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि बड़े पैमाने पर ऋण संकट देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक छोटी मंदी नहीं होने वाली है। यह गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली मंदी होगी।

निवेशकों के लिए सलाह रूबिनी ने निवेशकों को भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आपको इक्विटी पर अब ढील देने की जरूरत है।

आपके पास अधिक नकदी होनी चाहिए। वह लंबी अवधि के बॉन्ड से दूर रहने और शॉर्ट टर्म ट्रेजरी जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में निवेश की सलाह दे रहे हैं। बता दें कि नूरील रूबिनी ने 2007-2008 में आर्थिक मंदी को लेकर सटीक भविष्यवाणी की थी। इस वजह से उन्हें डॉक्टर डूम का नाम दिया गया था।

सचिन पायलट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुके हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी। ऐसे में सभी विधायकों के राजनीतिक स्वर बदलने लगे हैं, जिनमें अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक बाबूलाल नागर भी शामिल हैं, जिन्होंने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा कि वह तो खुद राजेश पायलट के कट्टर समर्थक रहे हैं। ऐसे में संकेतों से समझा जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान का इशारा किस ओर है।

दूसरी ओर जयपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को सरकारी निवास 8 सिविल लाइन पर बुलाया। इस दौरान बहुत से मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए, लेकिन बताया जाता है कि 7 - 8 मंत्री मुख्यमंत्री निवास नहीं पहुंचे। वहीं कुछ मंत्री सचिन पायलट से मिलने उनके सरकारी निवास भी पहुंचे। ऐसे में राजस्थान के तमाम राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं, जिसमें कि मंत्री और विधायकों का रुख भी बदलता नजर आ रहा है और वह अब बजाए और कहीं जाने की सीधे सचिन पायलट से मिलने उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहले जहां कोच्चि में राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद में दिल्ली जाकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से एक साथ मुलाकात करने वाले थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में 1 दिन के विश्राम के दौरान राहुल गांधी के दिल्ली आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली जाने के बजाए शिर्डी में साईं बाबा के दर्शन करने के बाद में सीधे जयपुर लौट आए। यहां आकर गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों से मुलाकात की है।

सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से दो दिन की राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि, न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर दो दिन बाद कार्यवाही की जा सकती है

- सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव के साथ मारपीट व अभद्रता के मामले में ये निर्देश दिए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक फरवरी 2022 को आदेश जारी कर न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक निलम्बन की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

जयपुर, 23 सितंबर (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन कमिश्नर यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ अभद्रता और मारपीट से जुड़े मामले में ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर को 2 दिन की राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि, वो न्यायिक जाँच की रिपोर्ट के आधार पर 2 दिन बाद सौम्या गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई करने को स्वतंत्र है।

जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय किशन कौल की खंडपीठ ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि, न्यायिक जांच रिपोर्ट में सौम्या गुर्जर को दोषी मान लिया गया है। ऐसे में स्पैशल लीव पैटिशन (एस.एल.पी.) को खारिज किया जाए।

गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने एक फरवरी 2022 को आदेश जारी कर, न्यायिक जांच कार्रवाई का नतीजा आने तक सौम्या गुर्जर के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद सौम्या ने वापस मेयर का पद संभाला था। दस अगस्त को न्यायिक जांच में, ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर, यज्ञिमित्र सिंह देव के साथ मारपीट व अभद्रता, मामले की न्यायिक जांच में ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर व तीन पार्षदों, अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा व पारस जैन को नगर पालिका अधिनियम की धारा 39(1) (डी) सहित अन्य प्रावधानों के तहत, दुराचरण, कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने व अभद्र भाषा के आरोप में दोषी माना गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी।

श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट आदेश रद्द कर दिया और आर.सी.ए. के चुनावों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आर.सी.ए. ने तीनों जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता बहाल कर दी और अब तीनों जिला संघ आर.सी.ए. की आगामी ए.जी.एम. में शामिल होंगे।

जयपुर, 23 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों को संबद्धता मामले में राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद इन तीनों जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आर.सी.ए.) ने न केवल बहाल कर दिया है, बल्कि आर.सी.ए. की आगामी एजीएम में भी तीनों संघ हिस्सा लेंगे। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए मामले को एकलपीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एकलपीठ को कहा है कि वह जल्द से जल्द मामले की सुनवाई पूरी करे। वहीं अदालत ने आर.सी.ए. के चुनावों पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सुनवाई के दौरान श्रीगंगानगर व अन्य जिला क्रिकेट संघ ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि आर.सी.ए. के चुनाव होने वाले हैं और इसकी आपत्ति लोकपाल के समक्ष होती है, लेकिन लोकपाल हाईकोर्ट के रिटायर जज हैं। जबकि नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही लोकपाल नियुक्त हो सकते हैं। ऐसे में मौजूदा लोकपाल की नियुक्ति गलत है तो फिर आपत्ति किसके समक्ष पेश करें।

इसलिए आर.सी.ए. के चुनाव पर रोक लगाई जाए। जवाब में आर.सी.ए. ने कहा कि उन्होंने तीनों जिला क्रिकेट संघों को पहले से ही नोटिस भेजकर एजीएम के लिए आमंत्रित कर रखा है और उनकी संबद्धता को भी बहाल कर दिया है। ऐसे में अदालत द्वारा आर.सी.ए. के चुनावों पर रोक नहीं लगाई जाए। इस पर क्रिकेट संघों की ओर से लोकपाल की नियुक्ति गलत होने व मौजूदा लोकपाल को हटाने के लिए कहा, लेकिन अदालत ने कहा कि यह मुद्दा हाईकोर्ट में लंबित है और इसमें वे दखल नहीं देना चाहते। गौरतलब है कि आर.सी.ए. ने पिछले दिनों श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता को निरस्त कर दिया था।

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर एकलपीठ ने नागौर व श्रीगंगानगर क्रिकेट संघ की संबद्धता रद्द करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन खंडपीठ ने लोकपाल को इस मामले में निर्णय लेने की छूट दे दी थी। खंडपीठ के आदेश को जिला क्रिकेट संघों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

ब्रिटेन और भारत में फ्री ट्रेड एग्रिमैंट डील क्यों फाइनल नहीं हो पा रही?

- इस डील के मामले में दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर की पाँच दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक क्रियान्विति नहीं हो पाई है।

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने ब्रिटेन की यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (एफ.टी.ए.) पर हस्ताक्षर होने के आसार हैं। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रिमैंट (एफ.टी.ए.) को लेकर पांच दौर की बातचीत हो चुकी है। ज्यादातर बातों पर सहमित बन गई है और बचे हुए कुछ मामलों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। माना जा रहा है कि दिवाली तक सहमति अपने अंतिम चरण में होगी, जो कि 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जानी है।

मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया, भारत और ब्रिटेन को विश्वास है कि दिवाली से एफ.टी.ए. पर सहमति बन जाएगी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में व्यापार मंत्रियों की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पी.एम. मोदी के ब्रिटेन दौरे की जानकारी अक्टूबर के पहले हफ्ते में सार्वजनिक की जा सकती है। यह यात्रा दिवाली के आसपास ही होने के आसार हैं। हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने हाल ही में कहा था कि दिवाली का त्योहार मनाने का सबसे अच्छा तरीका एफ.टी.ए. को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच एफ.टी.ए. समझौता होने से न सिर्फ आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलेगी, बल्कि रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे।

इस व्यापार समझौते पर दिवाली के त्योहार तक हस्ताक्षर हो जाने की काफी उम्मीद है। भारत और ब्रिटेन ने इस समझौते को दिवाली तक पूरा करने की जो समय सीमा तय की हुई है, वह एक शुभ तिथि साबित होगी।

उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजेंद्र रत्नू ने कहा कि दोनों ही देशों के नेता इस व्यापार समझौते को लेकर दृढ़प्रतिज्ञ हैं।

इस समझौते से कपड़ा, चमड़ा, आभूषण व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जैसे श्रम-बाहुल्य क्षेत्रों में भारत के निर्यात को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच अधिकांश उत्पादों और सेवाओं का व्यापार लगभग निःशुल्क हो जाएगा। इससे द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

गहलोत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिए वह जल्दी ही अपना नामांकन पत्र भरेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से पहले इस्तीफा देने की जरुरत नहीं है क्योंकि राहुल गांधी द्वारा उदयपुर संकल्प में व्यक्त किया गया ''एक व्यक्ति एक पद'' का सिद्धांत चुनाव जीतने के बाद ही अस्तित्व में आता है।

गहलोत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गांधी परिवार उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रुप में नहीं थोप सकता क्योंकि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शनिवार से जैसे ही नामांकन भरना शुरु होगा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा अपनी पावर का इस्तेमाल करना बंद हो जाएगा और यह निर्णय उनका स्थान लेने वाले अगले कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा ही लिया जाएगा।

उन्होंने यह भी संकेत दिए कि पार्टी के नए अध्यक्ष के रुप में वह राजस्थान कांग्रेस के विधायकों को ही यह निर्णय लेने देंगे कि वे किस नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और यदि विधायक पार्टी अध्यक्ष के नाते उन्हें यह अधिकार देते हैं कि वे किसी को मनोनीत करें तो इसके लिए किसी को मनोनीत कर देंगे क्योंकि यह कांग्रेस की बरसों पुरानी परम्परा रही है।

रूस के नागरिकों में देश छोड़ने की अफरातफरी मची

रूस के लोग कह रहे हैं कि, हमें बेवजह के युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है

मॉस्को, 23 सितंबर (वार्ता)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस से सैनिकों की आंशिक लामबंदी की घोषणा किये जाने के बाद से घबराये नागरिकों के देश छोड़कर जाने की होड़ सी लग गयी है।

बीबीसी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी। दूसरी ओर क्रेमलिन ने उम्रदराज लोगों के लड़ाई में भेजे जाने के डर से देश छोड़कर भागने की रिपोर्टों को अतिश्योक्तिपूर्ण बताया है, लेकिन जॉर्जिया की सीमा पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं जिसमें जंग से बचकर भागने की कोशिश कर रहे लोग शामिल हैं। कुछ लोग तो सीमा पर वाहनों की लंबी कतारों से बचने और पैदल ही सीमा पार करने पर लगी पाबंदी को देखते हुए साइकिलों पर ही सवार होकर सीमा पार करने की कोशिश में लगे हैं।

ऐसे ही एक व्यक्ति ने बीबीसी को नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर बताया कि वह गुरूवार सुबह नौ बजे से सीमा पार करने के इंतजार में था और देर रात वह सीमा पार करने में कामयाब भी रहा। एक अन्य व्यक्ति ने भी बताया कि उसने सीमा पार करने के लिए 12 घंटे का इंतजार किया।

प्रणय सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एस.ई.बी.आई.) को यह सूचना दे दी है कि वे एस.ए.टी. के 20 जुलाई के आदेश के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील दायर कर रहे हैं।

वस्तुतः एस.ए.टी. ने सेबी द्वारा किये गये 25 करोड़ रू. के जुर्माने को कम करके 5 करोड़ रू. कर दिया था।

रॉय दम्पति, जिन्होंने कुल मिलाकर 2000 करोड़ रू. का क्लेम किया है, उस समय से संकट में हैं, जब से उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने एन.डी.टी.वी. के शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के लिए बोली लगाई हैं। अडानी ग्रुप ने एन.डी.टी.वी. के शेयर हासिल कर लिये हैं तथा 26 प्रतिशत शेयर खरीदने की खुली पेशकश की घोषणा कर दी है।

उद्धव ठाकरे की बॉम्बे हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शिंदे गुट के इस अनुरोध को खारिज कर दिया कि वह याचिका पर तब तक कोई निर्णय ना करे जब तक कि पार्टी पर दावे के विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता।

शिंदे गुट के दादर विधायक सदा सरवंकर ने तर्क दिया था कि ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के याचिकाकर्ता इस याचिका के बहाने पार्टी पर दावा करने की कोशिश कर रहे हैं।

ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने यह कहते हुए निर्णय का स्वागत किया कि न्यायपालिका में उसकी आस्था सही साबित हुई है। पार्टी प्रवक्ता मनीष कायान्दे ने कहा कि इस वर्ष की रैली भव्य होगी।

उन्होंने दावे से कहा कि ब्रहन्मुम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (बी.एम.सी.) पर कुछ दबाव रहा होगा, जिसने अनुमति देने से इन्कार कर दिया था।

सेना के सचिव विनायक राउत ने कहा, ''न्यायपालिका में हमारा भरोसा पुख्ता एवं प्रमाणित हो गया है। पिछले कई सीलों से, दशहरा रैली ''शिव तीर्थ'' (सेना शिवाजी पार्क को इसी नाम से पुकाराती है) पर होती आ रही है लेकिन इस बार शिंदे गुट तथा भाजपा के जरिये इसमें रोड़े अटकान् की कोशिश की गई। लेकिन, अदालत ने इसे खारिज कर दिया।'' शिवसेना 1966 से ही हर साल दशहरा पर रैली आयोजित करती आ रही है। इस साल यह आयोजन इसलिये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सेना अब दो हिस्सों में बंट गई है तथा इसके अलावा, 2020 एवं 2021 में कोविड महामारी के कारण रैली नहीं हो पाई थी।

उद्धव ठाकरे ने अगस्त में शिंदे पर यह कहते हुये कटाक्ष किया था कि पार्टी को पूरा भरोसा नहीं है कि उसे इस आयोजन की अनुमति मिल जायेगी। ठाकरे ने यहां तक भी कह दिया था कि चाहे जो भी हो, वे शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेंगे।

शिवसेना की दशहरा रैली मुम्बई के शिवाजी पार्क में होगी। पूरे राज्य के शिव सैनिक इस रैली में पहुंचेंगे। ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुये कहा था, ''हम इन तकनीकी चीजों में नहीं जाते कि सरकार इसकी अनुमति देगी या नहीं। हम रैली जरुर आयोजित करेंगे। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग रैलियों का आयोजन करेंगे या नहीं। शिवसेना विश्वासघातियों के दम पर आगे नहीं बढ़ी, शिव सैनिकों के रक्त से आगे बढ़ी है।'' उम्मीद की जा रही है कि 5 अक्टूबर को होने वाली रैली में, वे महाराष्ट्र के विकास को लेकर लम्बा-चौड़ा भाषण देंगे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले विरोधी खेमे को बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में रैली के लिये अनुमति मिल चुकी है। एक धीर गंभीर राजनैतिक पर्यवेक्षक ने कहा कि उच्च न्यायालय की अनुमति ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना के इस दावे को और मजबूत करेगी, कि वह बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित राजनैतिक दल के वारिस हैं तथा उस पार्टी के परम्परागत अनुयायियों में निष्ठा पैदा करेगी, जो पार्टी देश की वित्तीय राजधानी में एक बड़ा राजनैतिक घटक रही है।

गहलोत तब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपेक्षाकृत युवा एवं ज्यादा गतिशील नेतृत्व लाना ही होगा, लेकिन काम में गहलोत एक बड़ा अवरोध सिद्ध हुये हैं। सूत्रों का कहना है कि वे अन्त तक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार गहलोत का सामना राहुल गांधी के उस उनम्य संकल्प से है तथा राहुल अब गहलोत की किसी भी बकवास को बर्दाश्त करने के मूड़ में दिखाई नहीं दे रहे।

नविका...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जस्टिस कृष्ण मुरारी की बैंच ने नविका कुमार को गत 8 अगस्त को दिया गया प्रोटेक्शन भी बढ़ा दिया। बैंच ने व्यवस्था दी कि उनके खिलाफ आठ हफ्तों तक कोई प्रतिरोधी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वे इस अंतरिम अवधि के दौरान कोई विधिक उपचार कर सकें।

बैंच ने उन्हें यह छूट भी दी कि वह मुख्य एफ.आई.आर. को खारिज करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं। दिल्ली पुलिस की इन्टैलीजेंस फ्यूजन एण्ड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन्स (आई.एफ.एस.ओ.) यूनिट इस मामले की जांच करेगी।

अपने खिलाफ शुरू की गई कार्यवाहियों को रद्द करवाने के लिए नविका कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से छूट प्रदान कर एक अंतरिम आदेश देते हुए केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किए थे।

नविका कुमार के टी.वी. शो की एक डिबेट के दौरान पैगम्बर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणियों का देशभर में विरोध हुआ था और कई खाड़ी देशों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

वो दिन गये जब

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐसे दौर में, जब जुबान फिसलने को भी पकड़ लिया जाता हो, तो सोचिये कि उस समय क्या हो सकता है, जब बहुत बड़े सार्वजनिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसी टिप्पणियाँ करते हुये देख लिया जाये। जैसाकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के साथ हुआ। नड्डा की इस टिप्पणी, कि मदुरै एम्स का 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, को लेकर उन पर चारों तरफ से हमले होने लगे हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने गुरुवार मदुरै में उद्योगपतियों की एक मीटिंग में बोलते हुये, यह दावा कर दिया कि मदुरै एम्स का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि इस एम्स के लिये एम.बी.बी.एस. की सीटें बढ़ाकर 250 कर दी गई है, जब पूर्व स्वीकृत सीटें केवल 100 थीं।

जब यह बयान तथ्य-जाँचकर्ताओं की जानकारी में आया तो वे तुरन्त उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ एम्स की बिल्डिंग बन रही थी। शुक्रवार को, पड़ोस की ही विरुधुनगर सीट के कांग्रेस सांसद एम.बी. मणिक्कम टैगोर तथा मदुरै सांसद वैंकटेशम (सी.पी.एम.) ने जब संबंधित स्थल पर एम्स का भवन दूढ़ा तो पता चला कि उस जगह पर तो एक ईंट तक नहीं थी।

कांग्रेस सांसद ने व्यंग्य शैली में ट्वीट किया, ''मदुरै एम्स (का निर्माण कार्य) 95 प्रतिशत पूरा कराने के लिये धन्यवाद। मैंने तथा मदुरै सांसद ने थोपुर साइट में एक घंटे तक भवन को दूढ़ा लेकिन कुछ नहीं मिला लगता है। एम्स की इमारत किसी ने चुरा ली है। .... सादर।''

इसके बाद, एक और ट्वीट में, कांग्रेस सांसद ने एक वीडिया साझा किया, जिसमें उन्होंने जानना चाहा कि भाजपा अध्यक्ष तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा इस प्रकार के मुद्दे पर आखिर झूठ कैसे बोल सके। कांग्रेस सांसद ने कहा, ''वे (भाजपा) इसी तरीके से तमिलनाडु तथा मदुरै की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं तथा तमिलनाडु इसे कभी नहीं भूलेगा।''

राजनैतिक विश्लेषक सी. रमन ने भी नड्डा की एम्स संबंधी घोषणा पर कटाक्ष करते हुये, ट्वीट किया, ''वाह! .... यह जानकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन यह एम्स किस शहर में है, महोदय? मदुरै में तो है नहीं।'' बहुत से लोगों ने ट्विटर के जरिये, प्रस्तावित स्थल से एम्स की इमारत के गायब हो जाने पर घोर आश्चर्य व्यक्त किया।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908